(b) All types of bouses have collapsed during the earthquake.

(c) No, Sir.

(d) Latur and Osmanabad area, as per ISI Code 1986, fall in Zone-I where intensity of 5 and below on the Modified Mer-calli Scale is expected in a probable earthquake. Therefore, seismicity being low, houses in this area were not declared unsafe.

कुछ नगरों को राष्ट्रीय नगर घोषित किया जाना

*27. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ नगरों को उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा वहां गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए "राष्ट्रीय नगर" घोषित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या योजना आयोग इन नगरों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए राज्यों को विशेष निधियां आबंटित करने का विचार रखता है; और

(घ) सरकार किन-किन नगरों को "राष्ट्रीय नगर" घोषित करने पर विचार कर रही है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) भारत सरकार किसी नगर को राष्ट्रीय नगर के रूप में घोषित नहीं करती। राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों, वर्तमान जनसंख्या, शहरी विकास दर और बड़े नगरों द्वारा राष्ट्रीय विकास में किए जाने वाले योगदान को ध्यान में रख कर बड़े नगरों के बुनियादी विकास के लिए योजना द्वारा एक केन्द्र प्रवर्तित योजना तैयार की गई है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर नगरों में बुनियादी विकास के लिए क्रमशः महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे गए थे।

बड़े नगरों के बुनियादी विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना सकल योजना आयोग द्वारा सिद्धान्त अनुमोदित की गई है। इस आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिकीकरण, योजना की चरणबद्धता, आठवीं योजना में शामिल किए जाने वाले वित्तीय परिव्यय और 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अपेक्षित धन दर्शाते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भेजने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों से वित्तीय विश्लेषण और नकद आमद, वित्तीय अपेक्षाओं और प्रत्याशित लाभ (वसूली) के विस्तृत ब्यौरे भेजने का भी अनुरोध किया गया है ताकि योजना की व्यवहारिकता प्रमाणित की जा सके।

Expenditure on Education in Terms of G.D.P.

*28 SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN:

SHRI SARADA MOHANTY :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it a fact that India ranks 115th in the world in the sphere of educational expenditure in terms of percentage of G.D.P.;

(b) what is the target date fixed to achieve for spending six percent of GDP on education as recommended by Kothari Commission almost three decades ago and subsequently supported by other Commissions and experts;

(c) what is the educational budgets of the Central and State Governments in terms of quantum and percentage of GDP during the last three years;

rd) whether it is a fact that the Central and State Governments spend Rs. 4,000 crores, approximately 25 percent of their educational budgets, on higher education

benefiting only 3.5 percent students of the entire student Community at the cost of primary and vocational educatiin; and

(e) whether Government propose to introduce easy Joan based higher education system as existing in several other countries and transfer the resources to primary and vocational education expended today on higher eduction ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) According to UNESCO Statistical Year Book 1992 India ranks 112th in terms of public expenditure on education as percentage of GNP; however, the Indian expenditure compares very favourable with that in the relevant peer group of other developing countries in Asia.

(b) and (c) The expenditure on Education of the Centre and States was Rs. 17193.66 crores in 1990-91, Rs. 19009.29 crores (RE) in 1991-92 and Rs. 20,750.09 crores (BE) in 1992-93. This expenditure as a percentage of GNP was about 3.6% during the period 1990-91 to 1992-93 as compared to 2.9% in 1965-66 when the Kothari Commission submitted its report. The national resolve has been to achieve the level of 6%. The achievement of this goal is linked with the overall availability of resources and the competing claims of other sectors.

(d) During the year 1992-93 an amount of Rs. 2631.98 crores has been provided for general higher education which forms 12% the total Education budget of the Central and State Governments. The enrolment in higher education in 1992-93 was *2.6%* of the total enrolment.

It is necessary to take a holistic view of the national system. Also, expenditure in one sector of education is not at the cost of other sectors. The Government gives the highest priority to Primary Education but higher education has its own importance as it provides qualified manpower for the national system.

(e) Commercial Banks are already providing educational loans to students panning tigher education. This facility is expected to increase with time.

जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ का कार्यकरण

*29. **श्री महादेव आनन्द पासवान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की स्थापना आदिवासियों के कल्याणार्थ की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय सहकारी विपणन संघ की सभी कर्मचारी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों की संख्या और उनका प्रतिशत कितना-कितना है;

(ग) बिहार में वित्तीय सहायता के माध्यम से आदिवासियों के उत्थान का कार्य कौन-कौन सी संस्थाएं कर रही हैं और उनसे लाभान्वित आदिवासियों की संख्या कितनी है;

(घ) बिहार में कौन-कौन से जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार अध्यक्ष को मनोनीत करने का विचार रखती है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) जी, हां।

(ख) निम्नानुसार :

श्रेणी	संख्या	प्रतिशतता
अनुसूचित जाति	56	19%
अनुसूचित जनजाति	46	15%
सामान्य	196	66%
कुल	298	